सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक 163 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, सोमवार 20 जुलाई, 2026
मूल्य ₹ 3/-

बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके।
-भगवान बुद्ध

रोहित बने लॉर्ड्स में शतक लगाने वाले... 7 | पंजाब में कांग्रेस को नहीं मिल रही... 3 | जौहर विवि को भाजपा सरकार... 2

संसद भवन तक पहुंच गये प्रदर्शनकारी

जगह-जगह बैरिकेटिंग और दिल्ली पुलिस के आंसू गैस के गोले

» अमित शाह से मिले धर्मेन्द्र प्रधान, क्या इस्तीफा होगा?

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आज दिल्ली में सिर्फ सड़कें ब्लाक नहीं हुईं बल्कि सरकार की ओर से उस नैरेटिव को ब्लाक करने की कोशिश की गयी जिसने उसकी नींद उड़ा दी। दिल्ली में एक तरफ संसद का मानसून सत्र चला तो दूसरी तरफ संसद की ओर बढ़ते हजारों कदम।

बीच में बैरिकेड पुलिस और धारा 163 के साथ मीडिया के अनगित कैमरे। आज ऐसा लगा कि जैसे पूरी राजधानी किसी वेब सिरीज की पालिटिकल फिल्मी स्टोरी का लाइव एपिसोड बन गयी हो। बस फर्क इतना है कि यहां स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं था जो कुछ भी हुआ वह लाइव हुआ है जो होगा लाइव होगा।

दिल्ली पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले

आज हम सब ने एक अजीब तस्वीर देखी संसद चल रही थी लेकिन संसद तक जाने वाला रास्ता बंद था। जंतर मंतर से निकले कदम बैरिकेडों पर थम गए। नारों की जगह धक्का-मुक्की की तस्वीरें वायरल होने लगीं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देती रही प्रदर्शनकारी लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते रहे। कुछ घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर वीडियो बयान और आरोपों की बाढ़ आ गई। काकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के संसद चलो आह्वान पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन पहुंच गए हैं। इस दौरान उनकी रास्ते में पुलिस से कई बार झड़प भी हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जबकि संसद भवन के सामने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए।

अब आंदोलन का अगला चरण क्या

यही वजह है कि अब आंदोलन का अगला चरण सिर्फ सड़क पर होने वाले विरोध तक सीमित नहीं माना जा रहा। एक तरफ सरकार के साथ संभावित संवाद की कोशिश है, तो दूसरी ओर राजनीतिक स्तर पर हो रही बैठकों को भी बारीकी से देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि क्या बातचीत टकराव की जगह ले पाएगी या फिर संसद के बाहर शुरू हुआ यह संघर्ष मानसून सत्र की पूरी राजनीतिक दिशा को प्रभावित करेगा। फिलहाल इतना तय है कि आंदोलन अब केवल नारों का नहीं, बल्कि बातचीत, रणनीति और राजनीतिक संदेश–तीनों का केंद्र बन चुका है।

सदन हंगामें की वजह से स्थगित होता रहा

विपक्ष का हंगामा नहीं थमने पर स्पीकर ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर में कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद यह सिर्फ सात मिनट तक चली और फिर विपक्ष की भारी नारेबाजी के बीच लोकसभा को दोबारा स्थगित कर दिया गया। उधर, रास में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। कुछ देर बाद विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसके कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे स्थगित करनी पड़ी। दोपहर में कार्यवाही शुरू होने पर महज एक मिनट सदन चला। दोबारा में कार्यवाही को 12.30 तक स्थगित किया गया।

हंगामे की भेंट चढ़े प्रश्नकाल और शून्यकाल

मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गए। नीट पेपर लीक मामले पर संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सदस्यों का हंगामा बरकरार रहा। इसके बाद सुबह 11 बजे से तीन बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 12.30 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस और अन्य दलों के सांसदों की नारेबाजी जारी रही। पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्ष के सदस्यों से कहा, सुबह से लगातार आप लोग सदन को बाधित कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बाढ़ से गंभीर हालात हैं और लोग परेशानी में हैं। ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। बाढ़ के मुद्दे पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने शून्यकाल बेहद महत्वपूर्ण समय होता है और सांसदों को मुद्दा उठाने का अवसर मिलता है। विपक्ष के सदस्यों का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। दिलीप सैकिया के बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इसके बाद सदन की कार्यकारी दोपहर एक बजे तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले, सुबह 11 बजे सत्र शुरू होने पर लोकसभा में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों से अनुरोध किया कि वे अपनी सीट पर बैठे रहें। सदन चलाने में सहयोग करें।

क्या इस्तीफा देंगे धर्मेन्द्र प्रधान

संसद मार्च के बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सत्र शुरू होने के पहले दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उनके इस्तीफे को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक सरकार या प्रधान की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

जेपी नड्डा से मिला सीजेपी प्रतिनिधिमंडल, शाह-प्रधान मुलाकात से तेज हुई सियासी अटकलें

संसद मार्च के बीच अब आंदोलन का दूसरा मोर्चा सड़क से निकलकर सत्ता के गलियारों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जंतर-मंतर और संसद के बीच प्रदर्शन, बैरिकेड और राजनीतिक टकराव की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ बातचीत की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए रवाना हुआ है। पार्टी का कहना है कि आंदोलन केवल विरोध तक सीमित नहीं है बल्कि समाधान के लिए सरकार के साथ बातचीत भी जरूरी है। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव

दास ने बताया कि आशुतोष सांका और वह स्वयं सरकार से बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार पार्टी की मांगें पहले दिन से स्पष्ट हैं और देशभर से बड़ी संख्या में युवा इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पार्टी संवाद के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी बातचीत का उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रमुख मांगों पर ठोस समाधान होना चाहिए। उनका दावा है कि आंदोलन अब किसी एक शहर या एक संगठन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं की भागीदारी ने इसे व्यापक स्वरूप दिया है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में एक और मुलाकात ने चर्चाओं को हवा दे दी।

जौहर विवि को भाजपा सरकार संकीर्ण राजनीति का शिकार न बनाए : अखिलेश

» सपा प्रमुख ने कैसरबाग में भाजपा के कार्यालय को लेकर भी सवाल उठाए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार जौहर विवि को लेकर भाजपा व उसकी सरकार पर हमला जारी है। सपा प्रमुख ने कहा है कि अपनी संकीर्ण राजनीति का शिकार न बनाए। उन्होंने कैसरबाग में भाजपा के कार्यालय को लेकर भी सवाल उठाए। पूर्व सीएम बोले भाजपा का अवैध दफ्तर बन रहा है, एलडीए संज्ञान ले।

सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव ने रामपुर के मो. अली जौहर विश्वविद्यालय के मामले में कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की युवाओं और उनके अभिभावकों की मुहिम में हम सब पूरी तरह से साथ हैं। बदले की भावना में जल रही भाजपा सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को अपनी संकीर्ण राजनीति का शिकार बनाने की कोशिश न करे। साथ ही कहा कि कैसरबाग में निर्माणाधीन भाजपा का दफ्तर अवैध है, लखनऊ विकास प्राधिकरण इसका संज्ञान ले।

अखिलेश यादव ने जौहर विवि के बारे में जारी बयान में कहा कि इस दुर्भावनापूर्ण पक्षपाती फैसले के खिलाफ हमारे साथ वे सब हैं, जिनके सपने पर बुलडोजर चलाने की निकृष्ट कोशिश भाजपा सरकार कर रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सच तो ये है कि भाजपा शिक्षा के ही विरुद्ध है, क्योंकि शिक्षित लोग जागरूक और प्रगतिशील होते हैं। वे अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। इसलिए भाजपाई और उनके संगी-साथी, प्राथमिक विद्यालय और अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय तक बंद करवाने की भूमिगत योजना बनाते रहते हैं।

यूनिवर्सिटी और छात्रों के भविष्य को बचाया जाए

उन्होंने कहा कि हम शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए देश भर से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ आएं। विश्वविद्यालय में हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं, क्या भाजपा अब हर समाज के युवाओं के विरुद्ध हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कुछ कागजी कमी है, तो उसके कागज पूरे करके यूनिवर्सिटी और छात्रों के भविष्य को बचाया जाए। यहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे भाजपाइयों की तरह अपने बच्चों को महंगे विश्वविद्यालय या विदेशों में पढ़ा सकें।

भाजपा सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता जानते हैं कि पढ़-लिखकर लोग नौकरी-रोजगार मांगेंगे, जो भाजपा सरकार देना ही नहीं चाहती है। इन अपंजीकृत लोगों के अपने सभी स्कूल-विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन दूसरों पर प्रतिशोध की भावना से एकतरफा कार्रवाई का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो अति निंदनीय है।

भाजपा ने भगवान राम के साथ धोखा किया : प्रमोद तिवारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने नीट घोटाले, पेपर लीक, जमीन घोटालों और इथेनॉल मिश्रण जैसे मुद्दों को भी विपक्ष की मुख्य चिंता बताया है, जो सरकार पर दबाव बनाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष संसद के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान कई मुद्दे उठाने की योजना बना रहा है, जिनमें अयोध्या राम मंदिर में दान के प्रबंधन में कथित अनियमितताएं सबसे पहला मुद्दा है।

तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर भगवान राम के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और कहा कि चंदे से जुड़े मुद्दे विपक्ष के लिए मुख्य चिंता का विषय हैं। उन्होंने नीट परीक्षा से जुड़े विवादों, पेपर लीक के आरोपों, जमीन के घोटालों और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के मुद्दों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसकी सरकार ने भगवान राम के साथ धोखा किया है। उन्होंने न सिर्फ दान का पैसा हड़पा, बल्कि लोगों की आस्था के साथ डकैती भी की है। इसीलिए हम इस मुद्दे को सबसे प्रमुखता से उठा रहे हैं। ये हालात जान-बूझकर पैदा किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय महत्व के अहम मुद्दों पर ध्यान दें : मायावती

» बसपा प्रमुख ने सत्ता पक्ष तथा विपक्ष से मॉनसून सत्र के दौरान संसद के सुचारू कामकाज का आह्वान किया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने आज से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के दौरान संसद के सुचारू कामकाज का आह्वान किया है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय महत्व के अहम मुद्दों पर ध्यान देने का आग्रह किया है।

सत्र से पहले एक्स पर एक पोस्ट में मायावती ने कहा कि देश यह देख रहा है कि क्या संसद में सार्थक चर्चा होगी या बार-बार कार्यवाही स्थगित होने और हंगामे की वजह से कामकाज में बाधा आएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मुद्दों पर गंभीर बहस और समाधान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब जबकि संसद का मॉनसून सत्र कल, 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, तो एक बार फिर देश और आम लोगों के मन में यह चिंता है कि क्या यह सत्र भी हंगामे, स्थगन और अव्यवस्था की भेंट चढ़ जाएगा, या फिर देश के ज्वलंत मुद्दों- जैसे बेतहाशा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं की असुरक्षा, अहम परीक्षाओं में पेपर लीक वगैरह - से पैदा हुए तनावपूर्ण, आक्रोशित और उत्तेजित माहौल को शांत करने और उनका संतोषजनक समाधान निकालने की कोई गंभीर कोशिश की जाएगी। मायावती ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और कुप्रबंधन से जुड़े विवाद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से जनता में भारी आक्रोश है और सत्र के दौरान यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। उन्होंने कहा कि वैसे, अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, उसमें हेर-फेर और गबन को लेकर जनता में जो भारी आक्रोश है, उसने उत्तर प्रदेश और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लोग चुनावी फायदे के लिए धर्म का राजनीतिकरण करने वालों से जवाबदेही मांग रहे हैं और लोगों का दिल दुखाने के लिए उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसकी गूंज सड़कों से लेकर अदालतों तक सुनाई दे रही है और यह मुद्दा संसद में भी निश्चित रूप से गरमाएगा, जिस पर लोगों की पैनी नजर है। उन्होंने संसद का ध्यान आकर्षित करने वाले कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का भी जिक्र किया, जिनमें पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद के हालात, राजस्थान में माताओं की मौत, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताएं, चुनाव के दौरान मुफ्त उपहार बांटने में कथित अनियमितताएं, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, पुलिस एनकाउंटर, लंबे समय से बसी कॉलोनियों को तोड़ा जाना और वैश्विक संघर्षों के कारण पैदा हुई आर्थिक चुनौतियां शामिल हैं।

परिसीमन बिल रोकने के लिए लगाएंगे पूरी ताकत : धर्मेन्द्र यादव

» सपा सांसद बोले- 75 साल से चले आ रहे लोकतांत्रिक ढांचे पर भरोसा क्यों नहीं है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी लोकसभा में परिसीमन प्रक्रिया में बदलाव करने वाले संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इस विधेयक में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है और इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 023 के तहत विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी शामिल है।

संसद के मॉनसून सत्र से पहले और सर्वदलीय बैठक के बाद, धर्मेंद्र यादव ने सत्ताधारी बीजेपी के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों को 75 साल से चले आ रहे लोकतांत्रिक ढांचे पर भरोसा क्यों नहीं है? वे परिसीमन बिल लाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव पहले भी इस बिल का पुरजोर विरोध करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, हम इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे।उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर भी टिप्पणी की, जो पहले ही पास हो चुका है। उन्होंने कहा कि असल मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है; वे बस इसका इस्तेमाल परिसीमन की प्रक्रिया को उलझाने के लिए करना चाहते हैं। संविधान (131वां संशोधन) बिल अप्रैल में 298 वोट मिलने के बाद गिर गया था। धर्मेंद्र यादव ने अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले चंदे में हेराफेरी के आरोपों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की।

चंदे में गड़बड़ी को लेकर सारे तथ्य सामने आने चाहिए

समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चंदे में गड़बड़ी को लेकर सारे तथ्य सामने आने चाहिए. सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, उस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठाए। धर्मेंद्र यादव ने कहा, एसआईटी कौन है? एसआईटी के सदस्य खुद फंसे हुए हैं। वो खुद सरकार के रहमो-करम पर हैं तो वो क्या निष्पक्ष जांच करेंगे?

यूपी चुनाव में अखिलेश नहीं देंगे शिवपाल को टिकट : राजभर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

» सुभासपा नेता ने फिर सपा प्रमुख को घेरा

लखनऊ। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर भोजपुरी में किए गए एक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि सपा में परिवारवाद का ठप्पा हटाने के लिए सफाई अभियान चलाने की चर्चा है।

राजभर ने अपने पोस्ट की शुरुआत व्यंग्यात्मक अंदाज में की। उन्होंने लिखा, का हो अखिलेश भइया, घर-परिवार में सब ठीक-ठाक चलत ह न? इसके बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें सुनने में आ रहा है कि इस बार अखिलेश यादव परिवारवाद की छवि से बाहर निकलने के लिए पार्टी में सफाई अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। राजभर ने लिखा कि समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा टिकट के दावेदार तो खुद अखिलेश यादव के परिवार के लोग हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर टिकट किस-किस का काटा जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा,चर्चा है कि इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले चाचा शिवपाल यादव का टिकट काटकर की जाएगी। उन्होंने आगे लिखा, शिवपाल यादव उम्रदराज नेता हैं और उन्होंने अखिलेश यादव को गोद में खिलाया है। ऐसे में बुढ़ापे में उन्हें गच्चा देना ठीक नहीं होगा। आखिर अखिलेश अपने चाचा की नाराजगी और श्राप क्यों लेना चाहते हैं। सुभासपा प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ने अपने पोस्ट में शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, शवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाकर अपनी और अपने बेटे की राजनीतिक राह बनाई थी, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ही उन्हें वापस समाजवादी पार्टी में लेकर आए। सभी जानते हैं कि शिवपाल यादव और आदित्य यादव के प्रति अखिलेश यादव के मन में कितना प्रेम है। पोस्ट के आखिर में राजभर ने अखिलेश यादव को सलाह देते हुए लिखा, अगर वास्तव में परिवारवाद का आरोप हटाना है तो एक साथ पूरे परिवार का टिकट काटकर उन्हें घर बैठा देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस बार वैसे भी परिवार के सभी विधायक और सांसद भूतपूर्व होने वाले हैं। सैफई वालों की सफाई करके कर्मठ सपाइयों को मौका दीजिए महाराज।

पंजाब में कांग्रेस को नहीं मिल रही राहत

नेताओं के मनमुटाव से शीर्ष नेतृत्व आहत

» बागी नेताओं से राहुल गांधी नाराज
» चन्नी को दिल्ली बुलाकर नहीं की मुलाकात
» जल्द हो सकता है बड़ा फैसला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। पंजाब में अगले साल चुनाव है। तेजी से राज्य में आप की जगह ले रही कांग्रेस में बवाल थम नही रहा है। पंजाब कांग्रेस में बगावत की विस्तृत रिपोर्ट राहुल गांधी के टेबल पर पहुंच चुकी है। वे अब इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से चर्चा करेंगे। उसके बाद इस मसले पर हाईकमान की ओर से अंतिम फैसला लिया जाएगा।

हालांकि नाराज नेताओं को हाईकमान ने दिल्ली बुला रखा था मगर राहुल गांधी ने बागी नेताओं के झंडाबरदार पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को मिलने का समय नहीं दिया। पार्टी सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी कार्यालय से चन्नी समेत अन्य नेताओं को संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने को कहा गया। उधर, केसी वेणुगोपाल को भी निर्देशित किया गया था कि वे वीरवार को नाराज नेताओं से बातचीत करेंगे और वीरवार को ही टिप्पणी समेत अपनी विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। सूत्रों ने बताया कि देर शाम वेणुगोपाल ने अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी कार्यालय को भेज दी है।

राजा के पक्ष में प्रभारी

प्रभारी भूपेश बघेल भी बुधवार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल से मिलकर उन्हें सौंप चुके हैं। जिसमें उन्होंने बताया है कि 29 में से 25 जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के समर्थन में हैं जबकि सात सांसदों में से चार सांसद वड़िंग के साथ हैं। रिपोर्ट में वड़िंग को अध्यक्ष बनाए रखने की सिफारिश की गई है। दूसरी ओर, दिल्ली बैठकों के समानांतर चन्नी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर 'सारा पंजाब चन्नी दे नाल' अभियान तेज किया। यह अभियान हाईकमान पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेसियों की इस बगावत और दबाव की रणनीति के चलते हाईकमान असहज है।

दिल्ली में सुरजेवाला सुखजिंदर सिंह रंधावा व चन्नी की भाग-दौड़

वेणुगोपाल से बैठक के दौरान असंतुष्ट खेमे ने अपना दबाव बनाए रखा मगर नाराज नेताओं से संगठनात्मक बदलाव की जिद छोड़कर चुनाव से पहले एकजुटता बनाए रखने पर जोर देने को कहा गया। इस पर नाराज नेताओं ने केसी को बताया कि वे सूबे में चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन और सीएम फेस की मांग क्यों कर रहे हैं?

बघेल की भूमिका पर भी सवाल

पार्टी सूत्र बताते हैं कि केसी से बैठक के दौरान नाराज नेताओं ने पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया। नाराज नेताओं का कहना था कि प्रभारी की ओर से उनकी बात सही ढंग से हाईकमान के समक्ष नहीं रखी गई। इसलिए वे हाईकमान से मिलना चाहते थे। बैठक में पंजाब संगठन की स्थिति, चुनावी तैयारियां और गुटबाजी पर विस्तार से चर्चा हुई।

बतौर सांसद एवं पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सांसद एवं पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, सांसद डॉ. अमर सिंह, विधायक परगट सिंह, विधायक सुखपाल सिंह खैरा समेत अन्य नाराज नेता दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिल्ली में इन नेताओं की मुलाकात राष्ट्रीय महासचिव एवं कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से भी हुई। उधर, केसी वेणुगोपाल ने सभी नेताओं से सामूहिक और वन-टू-वन मुलाकात कर इस पूरे विवाद में उनका पक्ष और राय जानी।

जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जे पर सियासी घमासान

कांग्रेस और नेकां में नेताओं के रहे उछल रहे बयान

» लोकभवन तक निकलेगी विरोध रैली
» केंद्र पर दबाव की राजनीति बनाने की योजना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के सियासी मोर्चे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल्ली में 20 जुलाई प्रदर्शन पर अभी असमंजस है किंतु कांग्रेस ने जम्मू की सड़कों पर अकेले ही हुंकार भरने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। कांग्रेस ने 19 जुलाई को जम्मू में लोकभवन तक विरोध रैली और प्रदर्शन का एलान किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ सीधे मुकाबले का बिगुल फूंकते हुए कांग्रेस ने जम्मू में अपनी ताकत दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है।

इस प्रदर्शन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नवनिर्वाचित विधायक, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जम्मू में इकट्ठा होकर लोकभवन की तरफ कूच करेंगे। पार्टी का साफ कहना है कि जम्मू-कश्मीर की जनता को उनके लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार वापस दिलाने के लिए अब और इंतजार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा

कांग्रेस जहां जम्मू संभाग में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने और स्थानीय जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जम्मू को केंद्र बना रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उछालकर सीधे संसद के भीतर और बाहर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति में है। इसके लिए दिल्ली के जंतर मंतर को केंद्र बनाने की कोशिश है।

कांग्रेस 19 को पार्टी मुख्यालय पर व्यापक प्रदर्शन करेगी

अलबत्ता कांग्रेस ने एनसी से अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। एनसी के 20 जुलाई को संभावित प्रदर्शन से पहले उसने 19 जुलाई को पार्टी मुख्यालय पर व्यापक प्रदर्शन के बाद जम्मू स्थित लोकभवन तक विरोध रैली निकालने की घोषणा कर दी है। कहा है कि रैली में पार्टी के प्रदेश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, सभी विधायक और पदाधिकारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होंगे। उपराज्यपाल के जरिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।

नेशनल कॉन्फ्रेंस का जंतर-मंतर दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शन

नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी मानसून सत्र के पहले जंतर-मंतर दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटी है। संभावित प्रदर्शन की कमान खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संभाल रखी है। सफलता के लिए उन्होंने इसी माह में पहले श्रीनगर और फिर जम्मू में विशाल जनसभा भी की थी। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि इस बार आर-पार की लड़ाई होगी। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उन्होंने 50 से अधिक विपक्षी राजनीतिक दलों को पत्र भी लिखा था लेकिन अभी तक कितनों ने समर्थन दिया यह स्पष्ट नहीं हो सका। ताज्जुब की बात है कि सरकार को बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस ने भी उनसे दूरी बना रखी है। उसने भी स्पष्ट नहीं किया है कि वह प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होगी की नहीं।

जनता अब भाजपा का सच समझने लगी है झांसे में नहीं फंसेगी

4PM विशेष साक्षात्कार

सुबह-सुबह उठते आप गोदी मीडिया के पत्रकार को फेसबुक पर धो रहे थे। क्या मामला था आप पत्रकारों से खफा क्यों रहते हैं?

न्यूज 24 के अखिलेश आनंद का पहला शो था उन्होंने भाजपा, कांग्रेस के बाद तीसरे व चौथे प्रवक्ता को मौका दिया। मुझे नहीं, तो मैंने कहा मैं चला जाता हूं। बाद में मुझे मौका दिया तो अखिलेश यादव पर कुछ गलत टिप्पणी करने लगे मैंने उन्हें टोका। और आजकल अंजना जैसे और कुछ एंकर बहुत खोखले हैं। हर बार एक बात कहते हैं आप पीएम पर सवाल उठाकर लोकतंत्र का अपमान करते जबकि वे ज्यादा अपमान करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आलोचना करने से विदेशों में लोकतंत्र का सम्मान बढ़ता है। आज के मीडिया में सबसे बड़ी बीमारी एंकर है। ऐसे ही एकबार मैंने कहा मंदिर से ज्यादा अस्पताल जरूरी है पर एंकर मुझ पर चिल्ला पड़ा कि मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन अयोध्या के एक महंत अस्पताल में भर्ती थे। आपरेशन सिंदूर में इन एंकरों ने पाकिस्तान पर कब्जा करवा दिया। जब मैंने इसपर कहा आप गलत कर रहे तो एक एंकर बोला कि हम सेना का जोश बढ़ा रहे हैं।

हाल ही में एक टीवी डिबेट शो के दौरान, जब एक बीजेपी प्रवक्ता ने आपके एक पुराने विवादास्पद बयान का जिक्र किया, तो आजतक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने आपको बीच में टोकते हुए कहा कि वह बयान बहुत शर्मनाक था, लेकिन उसे दोबारा डिबेट में न दोहराया जाए? ये क्या मामला था?

अक्सर लाइव शो में टीवी एंकर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को बोलने का अधिक समय देते हैं और विपक्ष के नेताओं के सवालों और कुतर्कों से दबाया जाता है? एकबार तो एक बहस में सभी को मौका दिया गया मेरा नंबर 25 मिनट बाद आया। मैं तो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता हूं। जिस पर अक्सर एंकर और मेरे बीच तीखी बहस होती है? एंकर सरकार का गुणगान करते हैं। जबकि मीडिया का काम है उन चीजों को दिखाए जो सरकार छिपाना चाहती है। भाजपा से ज्यादा तो लोगों का नुकसान ये एंकर कर रहे हैं जो सच नहीं दिखा रहे हैं।

क्या मामला था, सुना है आपको आजतक वालों ने बैन कर दिया है?

बहस में एक गोल टोपी वाले धार्मिक व्यक्ति आते है उनके बयानों पर मैंने आपत्ति की थी। इस पर आजतक की एंकर ने कहा वह पैनल में आए किसी भी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करेंगे इसी पर मैंने डिबेट छोड़ दिया था। मैंने बस इतना कहा था कुछ लोग गैर हिंदू होकर हनुमान भक्त होने का दावा करते हैं। तो वह अपना धर्म छोड़कर हिंदू बन जाएं। क्योंकि उनके यहां एक ही भगवान मानते हैं। इस तरह के बहस में आकर धार्मिक उन्माद न फैलाएं। इस पर एंकर उनपर ही पर सवाल उठाते हुए यह मांग करतें हैं कि यदि वह सच्चे हिंदू हैं, तो उन्हें मौलानाओं को भी वही चुनौती देनी चाहिए या मुस्लिम धर्म छोड़ने जैसी बातें कहनी चाहिए। इन्ही सबको लेकर मुझसे बहस हुई थी।

आजकल के एंकर व एंकरियों के बारे में आपकी क्या राय है?

आजकल के एंकरों में कोई ज्ञान नहीं है। वो बस मेकअप करके आते हैं जो लिखके दिया जाता है वो ही बोल देते हैं। कोई रिसर्च नहीं करते हैं। हालांकि आज भी 15-16 पत्रकार ऐसे हैं जो निष्पक्ष है रिसर्च करके डिबेट करते हैं। मैं प्रिंट का पत्रकार रहा हूं कई खबरें लिखता रहा हूं। साथ में मैंने एमए पत्रकारिता के छात्रों को पढ़ाया इसके लिए मैं खुद 4-5 घंटे पढ़ता था। पर आज ऐसा नहीं हो रहा है।

मेरे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समुदाय पर दिए गए विवादित बयान के मामले पर 4PM यूट्यूब चैनल के एडिटर संजय शर्मा के साथ बात में इंटरव्यू में राजकुमार भाटी ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया? उन्होंने अपने बचाव में कहा कि उनके भाषण के कुछ हिस्सों को चुनिंदा तरीके से एडिट करके उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार किया गया है? उनका इरादा किसी भी जाति, विशेषकर ब्राह्मण समाज का अपमान करना नहीं था, बल्कि वे केवल सामाजिक न्याय और भेदभाव खत्म करने की बात कर रहे थे? राजकुमार भाटी ने कहा कि अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी भी मांगी थी, और दावा किया कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था।

राम मंदिर चोरी मामले में आपकी क्या राय हैं?

अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावे और चंदे के कथित गबन/चोरी के मामले को लेकर मैंने भाजपा और संघ पर तीखे हमले किए हैं। राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिया गया चढ़ावा और चंदा चोरी/गबन हुआ है। इसे चोरी नहीं बल्कि डकैती कहें। जब भी दान चोरी जैसे मामले सामने आते हैं, पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करती है, लेकिन इस मामले में लीपापोती की जा रही है।

सीएम योगी तो इमानदार हैं तो उनपर चंदा चोरी में शामिल होने का आरोप कैसे लगा सकते हैं

सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संन्यासी होने और गोरखनाथ मंदिर की परंपरा का हवाला देते हैं, लेकिन राजनीतिक सत्ता में आने के बाद उन आदर्शों का पूरी तरह पालन नहीं करते। जो व्यक्ति संन्यासी का चोला पहनकर, मठ को छोड़कर राजनीति में आ जाए और सत्ता के लिए साधुता त्याग दे, उस पर किस हद तक विश्वास किया जा सकता है। राजनेता का काम जनता की भलाई है, जिसे वर्तमान सरकार पूरा करने में विफल रही है। वह कुछ लोगों की बात सुनते हैं। जबकि राममंदिर मामले में अब तक चंदा चोरों के यहां बुलडोजर चल जाना चाहिए था। पर ऐसा लगता है पैसा ऊपर तक गया है। इसकी लपट तो सीएम पर आएगी।

सपा के फायरब्रांड नेता व सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी से 4PM के संपादक संजय शर्मा ने बेबाक बातचीत की। उन्होंने आज की मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व वर्तमान गोदी मीडिया पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा का सच जान गई है। अब उसके झांसे में नहीं फंसेगी। चोरी व अपने पाप छिपाने के लिए योगी जी धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। पेशे से पत्रकार रहे और बाद में मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में प्रोफेसर भी रह चुके राजकुमार भाटी शुरू से ही संघर्षशील नेता रहे हैं। देहात मोर्चा से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। किसान आंदोलनों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं।

करियर की शुरुआत

भाटी ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1987 में गाजियाबाद के एक स्थानीय समाचार पत्र में पत्रकार के रूप में की थी? वह एक जाने-माने लेखक और स्तंभकार भी रहे हैं। पत्रकारिता में सक्रिय रहने के साथ-साथ, उन्होंने ग्रेटर नोएडा स्थित मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रोफेसर/शिक्षक के रूप में भी अध्यापन कार्य किया है? आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने के बावजूद, उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से वर्ष 1990 में राजनीति शास्त्र में परास्नातक और वर्ष 2007 में एलएलबी की डिग्री हासिल की।

राजनीतिक सफर

वह लगातार किसान आंदोलनों और सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहे हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में गिना जाता है। वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें गौतमबुद्धनगर की दादरी विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी भी बनाया था। वह उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी के रहने वाले एक साधारण किसान परिवार से आते हैं।

आप आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का तो इतना पैसा कहां जा रहा है?

इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। हर काम में 50 प्रतिशत कमिशन चल रहा है। जो एक्सप्रेस-वे सपा के समय में इतने साल पहले बना था वह अब तक बढ़िया चल रहा है। भाजपा के 9 साल में बने देश के हर बड़ा एक्सप्रेस-वे टूट गया। ये सिर्फ कमिशन की वजह से हुआ है। जो सड़के बन रही उनकी कीमत हमारी बनाई सड़कों की कीमत से दुगुना हैं। अगर गोरखपुर मठ की जांच की जाए तो नौ साल में उसकी प्रॉप्रटी कई गुना बढ़ी है। सीएम योगी की कार्यशैली में पक्षपात है। सरकार में जनता वास्तविक रूप से परेशान है। भ्रष्टाचार तो इस सरकार में कई गुना हो गया है।

सीए योगी ने कहा है कि सपा हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाएगी ऐसे आपकी पार्टी भाजपा के नमाज व रोजा इफ्तार के नैरेटिव को कैसे तोड़ेगी?

सीएम योगी झूठ बोलते हैं। सपा ने कभी वहां पर नमाज नहीं पढ़वाया। ये केवल धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। मुझे लगता है मंदिर में योगी जी की सहमति से डकैती हुई है। ऐसा न होता तो जिस अविनाश शुक्ला के घर से 80 लाख बरामद हुए थे उसी दिन उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए था। योगी जाति व धर्म देखकर फैसले करते हैं। सीएम कई बार यहां तक सदन में भी कह चुके हैं कि सपा सरकार अधिकतर थानों में केवल यादव थानाध्यक्ष बनाए गए थे जबकि वह इसका आंकड़ा नहीं दे पातें। अब लोग सबकुछ जान गए है बीजेपी के चक्कर में नहीं फसेंगे। भाजपा द्वारा आगामी चुनावों से पहले जनता को भड़काने और हिंदू-मुसलमान की राजनीति करने की रणनीति बनाती है। ऐसे बयानों के जरिए बेरोजगारी, महंगाई और घोटालों जैसे असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है।

भाजपा कहती है सपा मुस्लिमों की पार्टी है। वो अखिलेश को मौलाना और नेता जी को मुल्ला कहती है। इसकी काट सपा कैसे निकालेगी?

अखिलेश यादव और उनकी पार्टी सभी वर्गों की सच्ची हितैषी हैं। उनकी पार्टी बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों के विकास के लिए काम करती है। भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का काम करती है अखिलेश मुसलमानों, दलितों व पिछड़ों के अधिकारों का रक्षक हैं। सैफई में पूरा परिवार हर त्योहार में पूरे सांस्कृतिक विधान से त्योहार मनाता है। नेताजी (मुलायम सिंह यादव) नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करते थे, मंदिरों में जाते थे, और मंगलवार का व्रत भी रखते थे। पूरा सैफई परिवार पूरी निष्ठा से पूजा-पाठ और व्रत करता है।

भाटी जी आप ब्राहम्णों को बहुत कुछ कह देते हैं। वो बेचारे किसी तरह पूजा-पाठ करके अपना जीवन यापन कर रहे उन्हें क्यों आप परेशान कर रहे हैं?

आस्था और पूजा व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन धर्म-कर्म को अंधविश्वास या पाखंड से जोड़ना ठीक नहीं। मंदिर में भगवान को हाथ जोड़ों पर उसके नाम मुर्खता सही नहीं है। किसी को भी अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने या मानने का पूरा हक है, लेकिन धर्म के नाम पर पाखंड, अंधविश्वास, और समाज में ऊंच-नीच फैलाने की मानसिकता को वे मूर्खता या तर्कहीन हैं। उनका उद्देश्य किसी जाति या धर्म का अपमान करना नहीं है, बल्कि वे केवल रूढ़िवादिता और पाखंड के खिलाफ हैं। कोई इन बातों को अपने से जोड़ ले तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं।

ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित रूप से विवादित टिप्पणी पर बवाल

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने एक जनसभा में ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित रूप से विवादित टिप्पणी की थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा था, न तो ब्राह्मण अच्छा होता है और न ही कोई तवायफ। इस बयान को लेकर टीवी डिबेट्स में उनकी एंकर और बीजेपी प्रवक्ताओं से काफी तीखी बहस हुई थी। विवादित बयान पर उनके खिलाफ गाजियाबाद के कविनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 196(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बयान का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक दलों में भारी आक्रोश फैल गया था। बयान को लेकर पार्टी के भीतर भी घमासान मच गया था। सपा विधायक संतोष पांडे ने इसे अनुशासनहीन और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं, बीएसपी प्रमुख मायावती और कांग्रेस नेताओं ने भी अखिलेश यादव से भाटी को बर्खास्त करने की मांग की थी। विवाद बढ़ता देख अखिलेश यादव ने राजकुमार भाटी को कड़ी हिदायत दी थी, जिसके बाद भाटी ने बिना शर्त माफी मांग ली थी।

अंजना ओम कश्यप के शो हल्ला बोल में जोरदार बहस की

आजतक पर एंकर अंजना ओम कश्यप के शो हल्ला बोल में जब यह मुद्दा उठा, तो राजकुमार भाटी की बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और अन्य मेहमानों से जोरदार बहस हुई। भाटी ने सफाई दी कि उनके भाषण के कुछ हिस्सों को चुनिंदा तरीके से एडिट करके गलत प्रचार किया गया है। भाटी अपनी पार्टी का पक्ष जोरदार तरीके से रखते हैं और विपक्ष के दांत खट्टे कर देते हैं।

अखिलेश को भाजपा वाले गलत तरीके से पेश करते हैं इसपर आपकी क्या राय हैं?

भाजपा गलत चीजें फैलातीं हैं। हाल में मेरठ में पुलिस कप्तान ने एक दलित व्यक्ति को थप्पड़ मारा। हमारे नेता अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। उनके परिवार से मिले। पीड़ित परिवाारें को मुआवजा तक प्रदान किया। जबकि बहन जी पुलिस के समर्थन में दिखाई दीं। इस सरकार में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली ठीक नहीं है। दलित और वंचित समाज के उत्पीड़न और जातीय अहंकार दिखता है। पुलिस कानून के तहत कार्रवाई करने के बजाय खुलेआम मारपीट और गाली-गलौज पर उतर आई, जो किसी भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में निंदनीय है।

मुलायम सिंह पर अयोध्या में गोली चलवाले का आरोप लगाते हैं पर उनके समय में प्रमुख सचिव नृपेन्द्र मिश्रा थे। उन्हीं को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई उनके बनवाए गए मंदिर की छत टपक गई। आप उनकी गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं करते है?

जब अयोध्या में वह घटना घटी तब राज्य के सीएम नेता जी थे। नेता जी (मुलायम सिंह यादव) ने जो भी निर्णय लिया या जो भी कार्य किया, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया। क्योंकि ढांचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की सरकार की थी। नृपेन्द्र मिश्रा तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया उन्होंने कानून व्यवस्था के लिए गोली चलवाई।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

डिजिटलीकरण के खतरे से निपटने को बनाना होगा तंत्र

आजकल डिजिटज अरेस्ट व साइबर ठगी की खबरें आम होती जा रही है। जैसे-जैसे सरकार डिजिटलीकरण बढ़ा रही है वैसे ही खतरे भी बढ़ रहे हैं। इससे आमजन को आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमारी डिजिटल पहचान ही किसी और के हाथों लग जाए तो नुकसान केवल बैंक खाते तक ही सीमित नहीं रहता। कुल मिलाकर डिजिटलीकरण के खतरे से निपटने को बनाना तंत्र होगा। पहचान के साथ-साथ हमारा भरोसा और पूरी वित्तीय दुनिया ही खतरे में पड़ जाती है। यह खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि साइबर अपराध अब चोरी या ठगी भर नहीं रह गए बल्कि डिजिटल युग में नागरिकों के भरोसे पर सबसे बड़े हमले के रूप में सामने आ रहे हैं। इस खतरे की गंभीरता को हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिपोर्ट ने रेखांकित किया है। पर उसको रोकने के लिए काम करना होगा। रिपोर्ट में चेताया गया है कि हैकर अब केवल पासवर्ड या ओटीपी चुराने तक सीमित नहीं हैं।

वे सेशन हाईजैकिंग और इंफोस्टीलर जैसे नए हथियारों से सीधे उपयोगकर्ता की सक्रिय डिजिटल पहचान पर कब्जा कर रहे हैं। आप बैंकिंग ऐप या वेबसाइट में लॉगिन कर चुके हैं, उसी सक्रिय सत्र पर हैकर कब्जा कर लेता है। तकनीकी दुनिया में इसे सत्र अपहरण(सेशन हाईजैकिंग) कहा जाता है। इस रिपोर्ट में वित्तीय संस्थानों को अगले 18 महीनों का सुरक्षा रोडमैप भी सुझाया गया है। साफ है कि खतरा भविष्य का नहीं, हमारे सामने खड़े वर्तमान का ही है। डिजिटल भुगतान में दुनिया भारत की मिसाल देती है। यूपीआइ और ऑनलाइन बैंकिंग ने करोड़ों लोगों का जीवन आसान बनाया है। लेकिन हर महीने अरबों रुपए के लेन-देन की यह अपूर्व गति और डेटा का विशाल महासागर ही हमें साइबर अपराधियों का निशाना बनाता है। खतरे की गंभीरता इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसमें गलती हमेशा ग्राहक की नहीं होती। कोई संक्रमित लिंक, फर्जी ब्राउजर एक्सटेंशन, मालवेयर या असुरक्षित डिवाइस आपकी सक्रिय पहचान को ही अपराधी के हाथों में सौंप सकता है। जाहिर है साइबर सुरक्षा का मूलमंत्र अब मजबूत पासवर्ड और गुप्त ओटीपी नहीं रहा। ऐसे में केवल सावधान रहिए कह देना पर्याप्त नहीं है। अब वित्तीय संस्थानों को पारंपरिक सुरक्षा चक्रव्यूह से बाहर निकलकर जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर अपनाना होगा- जिसका मूल मंत्र है-कभी भरोसा मत करो, हमेशा सत्यापित करो। इसके साथ ही हर लेन-देन, हर डिवाइस और हर असामान्य गतिविधि की बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स और एआइ आधारित रियल-टाइम निगरानी अब अनिवार्यता बन चुकी है।

“ साइबर अपराध अब चोरी या ठगी भर नहीं रह गए बल्कि डिजिटल युग में नागरिकों के भरोसे पर सबसे बड़े हमले के रूप में सामने आ रहे हैं। इस खतरे की गंभीरता को हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिपोर्ट ने रेखांकित किया है। पर उसको रोकने के लिए काम करना होगा।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

वहां सुशासन की नई क्रांति का सूत्रपात हो

ललित गर्ग

भारत की पहचान केवल उसकी प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक दर्शन से नहीं है, बल्कि उन मंदिरों से भी है जो करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और जीवन का आधार हैं। अयोध्या का श्रीराम मंदिर, बद्रीनाथ धाम, माता वैष्णोदेवी, तिरुपति, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, सालासर बालाजी, खाटू श्यामजी जैसे मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा के जीवंत प्रतीक हैं। इन मंदिरों में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु इस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि यहां उन्हें केवल भगवान के दर्शन ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और नैतिक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। लेकिन जब इन्हीं मंदिरों से चढ़ावे की चोरी, वित्तीय अनियमितताओं, वीआईपी संस्कृति, पुजारियों अथवा कर्मचारियों के अनुचित आचरण और श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सामने आती हैं, तब केवल कोई संस्था बदनाम नहीं होती, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था घायल होती है।

हाल के वर्षों में श्रीराम मंदिर, बद्रीनाथ और अब माता वैष्णोदेवी मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मंदिरों की व्यवस्था को केवल धार्मिक भावना के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जिस धन को श्रद्धालु भगवान का अर्पण मानकर समर्पित करते हैं, वह किसी व्यक्ति या समूह की निजी संपत्ति नहीं है। उस धन का प्रत्येक रुपया सार्वजनिक विश्वास की धरोहर है। यदि उसी में अपारदर्शिता या चोरी का संदेह पैदा हो जाए तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि धार्मिक विश्वास के साथ विश्वासघात है। मंदिरों में बढ़ती अव्यवस्था का दूसरा गंभीर पक्ष है- वीआईपी दर्शन संस्कृति। आज देश का सामान्य श्रद्धालु कई-कई घंटे कतार में खड़ा रहता है। वृद्ध, महिलाएं, दिव्यांग और छोटे बच्चों के साथ आए परिवार कठिन परिस्थितियों में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मंत्री, विधायक, अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति पहुंचता है, सामान्य दर्शन रोक दिए जाते हैं और वीआईपी दर्शन शुरू हो जाते हैं। आम श्रद्धालु की लाइन रोक दी जाती है, उसके दर्शन का समय बाधित होता है और उसे यह एहसास कराया जाता है कि भगवान के दरबार में भी सभी बराबर नहीं हैं।

यह स्थिति भारतीय संस्कृति और धर्म की मूल भावना के विपरीत है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर के समक्ष राजा और रंक में कोई भेद नहीं होता। यदि मंदिरों में भी सामाजिक और राजनीतिक विशेषाधिकार का प्रदर्शन होगा तो यह

धर्म के मूल स्वरूप का अपमान है। मंदिरों को लोकतांत्रिक समानता और आध्यात्मिक समरसता का सर्वोच्च उदाहरण बनना चाहिए, न कि सामाजिक असमानता का मंच। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में 'समान मन्दिर दर्शन नीति' लागू की जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा या अत्यंत विशिष्ट संवैधानिक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को सामान्य श्रद्धालुओं की कतार से अलग विशेष दर्शन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यदि किसी कारणवश सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक हो, तब भी आम श्रद्धालुओं के दर्शन बाधित नहीं होने चाहिए। भगवान के दरबार में सबसे बड़ा वीआईपी केवल श्रद्धा होनी चाहिए, पद और सत्ता नहीं। इसी प्रकार मंदिरों की चढ़ावा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। आज डिजिटल भारत का युग है, फिर भी अनेक मंदिरों में दान और चढ़ावे की पारदर्शी व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी है। प्रत्येक बड़े मंदिर में दान-पात्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, सीसीटीवी कैमरे, बारकोड आधारित सीलिंग, नियमित स्वतंत्र ऑडिट तथा प्रत्येक माह आय-व्यय का सार्वजनिक विवरण वेबसाइट और सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। श्रद्धालु को यह जानने का अधिकार है कि उसके द्वारा दिया गया धन कहां और किस उद्देश्य में उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन में केवल धार्मिक पहचान ही नहीं, बल्कि चरित्र, ईमानदारी और प्रशासनिक दक्षता को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंदिर प्रबंधन समितियों में ऐसे व्यक्तियों को स्थान मिले जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा निष्कलंक हो, जिनका सार्वजनिक जीवन पारदर्शी रहा हो और जिन पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या आपराधिक आरोप न हों। समय-समय पर उनके कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन भी किया जाए। मंदिर प्रबंधन किसी का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व है।

मंदिरों में सेवा करने वाले पुजारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी आचार-संहिता बनाई जानी चाहिए। श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा, दलालों से मिलीभगत, नशाखोरी या किसी भी प्रकार का अनुशासनहीन व्यवहार पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई हो। सालासर बालाजी में बाउंसरों द्वारा श्रद्धालु की पिटाई और खाटू श्यामजी में मुख्य पुजारी से जुड़े विवाद जैसे प्रसंग यह संकेत देते हैं कि केवल धार्मिक पहचान पर्याप्त नहीं, बल्कि नैतिक अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है।

'मैहर' राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में

किसी महामारी के कारण मैहर में अनाथ बच्चों को देख दरबार के संगीतकार बाबा अल्लाउद्दीन खां का कलाकार मन विचलित हो उठा। तब उन्होंने उन यतीम बच्चों को संगीत सिखाना शुरू किया। प्रशिक्षण सफल होने लगा तो उत्साहित बाबा ने एक ऑर्केस्ट्रा बनाया, वही समूह आगे चलकर मैहर बैंड के रूप में छा गया।

राजेश गनोदवाले

देश में मॉनसून छाने के कुछ पहले आई यह खबर मन शीतल करने वाली है। समाचार है कि अब विश्वविख्यात 'मैहर बैंड' भारत सरकार की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दर्ज हो गया है। यानी अब हम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से बस एक कदम पीछे हैं। यह उपलब्धि केवल मैहर या विंध्य क्षेत्र की नहीं, पूरे मध्यप्रदेश और भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत के लिए उम्मीद लाई है। विस्तृत अर्थों में यह शास्त्रीय संगीत की उस सोच का सम्मान है, जिसमें दुर्लभता के प्रति नमन भाव बाहर आता है। नि:संदेह, इस बढ़त से भारतीय विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के देशीय प्रयासों में ऊर्जा आएगी, साथ ही उस दिशा को देखने वाले रास्ते भी चौड़े होंगे। उत्तर भारतीय रागदारी संगीत से जुड़ी यह खबर तब और सुखदाई है जब भारत की शास्त्रीय बिरादरी में दुर्लभता को लेकर एक प्रकार का ठण्डापन पसरा है।

आज शहनाई, दिलरुबा, तार शहनाई, इसराज और सारंगी या पखावज के प्रति आयोजन-समाज के भीतर कितनी गर्मजोशी है, बताने की जरूरत नहीं। जान लें, मैहर बैंड भारतीय वाद्य यंत्रों का ऐसा समूह है, जिसमें कुछ वाद्य इस बैंड के साथ ही जन्में। अर्थात उनका पहले कोई अस्तित्व नहीं था। इस आर्केस्ट्रा के जनक सरोद वादक बाबा अल्लाउद्दीन खां थे। अपनी कल्पनाशीलता से जब उन्होंने वाद्य यंत्रों के समूह के माध्यम से रागदारी बजाने, सुनवाने की परिकल्पना की तो पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ कुछ नवाचार भी जोड़ा। यही नवाचार दुर्लभ बन गया जब देश ने देखा कि लौह, पीतल के कुछ साधारण से पाइप भी सुर निकास में बराबरी का योगदान दे रहे हैं! मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक शहर से जुड़ी इस अनूठी शास्त्रीय परम्परा की कड़ी प्रसिद्ध मैहर घराना से संबंधित है। एक समय सिमटा-सा कस्बा मैहर बाबा अल्लाउद्दीन खां की कर्मभूमि था। उन्हीं बरसों में बाबा ने सन 1918 में इसे साकार किया था।

बैंड और मैहर शहर का गठजोड़ लेते दिया गया सुंदर परिचय मैहर बैंड के अस्तित्व में आने की कहानी भी खासी मर्मस्पर्शी है। असल में किसी महामारी के कारण मैहर में एकाधिक अनाथ बच्चों को देख दरबार के संगीतकार बाबा अल्लाउद्दीन खां का कलाकार मन विचलित हो उठा। तब उन्होंने कुछ सोचते हुए उन यतीम बच्चों को संगीत सिखाना शुरू किया। प्रशिक्षण सफल होने लगा तो उत्साहित बाबा ने एक ऑर्केस्ट्रा बनाया, वही समूह आगे चलकर मैहर बैंड के रूप में छा गया। राज दरबार के शासक राजकुमार ब्रजनाथ सिंह की हरी झंडी ने बाबा के इस रुझान को उठान दे दी, नतीजा पांचों वक्त के नमाजी और पहाड़ी पर विराजित मां शारदा के प्रतिदिन बिला नागा दर्शन करने जाने वाले बाबा का रचनात्मक मन सक्रिय हो उठा।

मैहर बैंड की सबसे बड़ी विशेषता नलतरंग वाद्य है, जिसे बंदूक की नलियों को स्वरबद्ध कर बनाया गया था - इसे दुनिया का एकमात्र ऐसा शास्त्रीय वाद्य माना जाता है। सितार, सरोद, वायलिन, चेलो, तबला जैसे वाद्यों का समन्वय इसकी पहचान है। बता दें कि संगना यानी संगीत नाटक अकादमी भारत में यूनेस्को की नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन संगना ने ही मध्य प्रदेश की तीन विरासतों को इस महत्वपूर्ण दायरे में लिया है। प्रदेश पर्यटन मण्डल ने इसी वर्ष 8 जनवरी, सन 2026 को मैहर बैंड के अलावा अगरिया लौह परंपरा और निमाड़ के जनपदीय भोजन को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव अकादमी को भेजा था।

अब इन तीनों विरासतों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कराने के दावे को आधिकारिक रूप से बल मिला है। अब आगे क्या? तो इसी राष्ट्रीय सूची में से चयनित विरासतों का नामांकन प्रत्येक दो वर्ष में यूनेस्को भेजा जाता है। इस सोच के पीछे खड़ी राज्य सरकार की बांछें खिलनी ही थीं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, सचिव डॉ. इलैयाराजा टी. इसे पीढ़ियों से संजोकर रखी गई हमारी सांस्कृतिक प्रणालियों की बड़ी मान्यता मानते हैं। संस्कृति मंत्री भी चिंता अब खत्म हुई वाले मोड में होंगे, कारण सत्ता की पहल के बाद ही तो सुध ली गई है। दो राय नहीं कि भारत भवन बनने के बाद प्रदेश में संस्कृति के विस्तार की जो व्यापक दृष्टि तत्कालीन सचिव, अशोक वाजपेई ने दी थी यह उसी का एक विलंबित विस्तार है। नि:संदेह, बाबा के पौत्र और उनकी अगली पीढ़ियों के लिए भी अब अपने पूर्वज के इन साक्षात चिन्ह को संरक्षित करने की मंशा से मन में कोई कल्याणकारी स्वर बजा होगा।

राम मंदिर मामले में पीएम की चुप्पी अस्वीकार : राहुल

चंदे की कथित चोरी को लेकर कांग्रेस व सपा अब भी हमलावर

» खरगे व लोस नेता प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। अयोध्या राम मंदिर चंदे की कथित चोरी को लेकर रार नहीं रूक नहीं रही है। कांग्रेस से लेकर सपा तक अभी भाजपा पर हमलावर है। इस बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अयोध्या राम मंदिर चंदे की कथित चोरी की स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग की है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और कहा कि लाखों श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई दान करके ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की चुप्पी स्वीकार्य नहीं है। अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित चोरी को लेकर मचे विवाद के बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की जांच की मांग की।

उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत की कमाई आस्था के साथ दान करने वाले लाखों श्रद्धालु चोरी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं ने अपने पत्र में कहा कि आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हज़ारों करोड़ रुपये की चोरी के बारे में जानते हैं। जिन लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था, भक्ति और भरोसे के साथ अपनी मेहनत की कमाई दान की थी, वे इस चोरी से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर संसद में ट्रस्ट बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके सदस्य पूरी तरह से उनकी सरकार ने ही नियुक्त किए थे। उन्होंने कहा कि आपने भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर संसद में ट्रस्ट बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके सदस्य पूरी तरह से आपकी सरकार ने ही नियुक्त किए हैं। यह बात सबको पता है कि ट्रस्ट के सदस्य संघ, वीएचपी और उनसे जुड़े संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसके बदनाम पूर्व जनरल सेक्रेटरी भी आपके करीबी सहयोगी थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी स्वीकार्य नहीं है और उनसे जवाबदेही तय करने और भरपाई सुनिश्चित करने की मांग की।

जवाबदेही तय करना और नुकसान की भरपाई करवाना पीएम की जिम्मेदारी : खरगे

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ऐसे अपराध के मामले में आपकी चुप्पी मंजूर नहीं है। जवाबदेही तय करना और नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की तुरंत एक स्वतंत्र और व्यापक जांच का आदेश दें, जिसमें नकद, सोना और चांदी समेत सभी चढ़ावों के प्रबंधन की जांच भी शामिल हो। उन्होंने यह भी मांग की कि जांच के नतीजे और ट्रस्ट के हिसाब-किताब को सार्वजनिक किया जाए ताकि हर भक्त को पता चल सके कि उनके चढ़ावे का इस्तेमाल कैसे किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जो भी लोग इसके लिए ज़िम्मेदार पाए जाएं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, चाहे उनका पद या प्रभाव कुछ भी हो। आपकी सरकार और ट्रस्ट की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी पारदर्शिता और तेज़ी से कार्रवाई करते हैं। भारत की जनता सब देख रही है। जय हिंद! पत्र में लिखा है कि जांच के नतीजे और ट्रस्ट के हिसाब-किताब को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि हर भक्त को पता चल सके कि उनके चढ़ावे का इस्तेमाल कैसे किया गया है।

सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन का हो रहा प्रचार, जींद की पीड़ा पर सरकार चुप : राव नरेंद्र

» कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीबीजी प्लांट से प्रभावित लोगों का मुद्दा उठाया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने जींद में पीएम नरेंद्र मोदी के हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर केंद्र सरकार ग्रीन एनर्जी का प्रचार कर रही है वहीं दूसरी ओर जींद के गोहाना रोड स्थित रिलायंस के सीबीजी प्लांट से प्रभावित लोगों की आवाज अनसुनी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े तीन महीने से स्थानीय लोग प्लांट के खिलाफ धरना दे रहे हैं।

राव ने आरोप लगाया कि घनी आबादी के बीच स्थित यह प्लांट जहरीले धुएं, बदबू और रसायनों के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। इससे अस्थमा, गले के संक्रमण की समस्याएं बढ़ रही हैं। यहां संपत्तियों के दाम गिर रहे हैं और लोग पलायन को मजबूर हैं। प्लांट से पर्यावरण, हवा और भू-जल भी प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि रिलायंस सीबीजी प्लांट का संचालन तत्काल बंद किया जाए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निष्पक्ष ऑडिट कराया जाए और प्लांट को आवासीय क्षेत्र से हटाकर उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। इस मुद्दे पर जरूरत पड़ने पर कांग्रेस आंदोलन शुरू करेगी।

रोहित बने लॉर्ड्स में शतक लगाने वाले पहले भारतीय

» हिटमैन किसी एक देश की धरती पर सर्वाधिक शतक लगाने वाले बने पहले भारतीय खिलाड़ी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लंदन। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शानदार बल्लेबाजी की। रोहित ने अपने वनडे करियर का 34वां शतक लगाया। दिलचस्प बात यह है कि रोहित लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर वनडे में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। जैकब बेथेल ने हालांकि, रोहित को अपना शिकार बनाया जो 110 गेंदों पर 17 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 138 रन बनाकर आउट हुए। रोहित लॉर्ड्स में सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाने वाले भारतीय बन गए। रोहित ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।

गांगुली ने 2004 में लॉर्ड्स में 90 रन बनाए थे, लेकिन रोहित ने इस रिकॉर्ड को अब अपने नाम कर लिया है। इस सूची में तीसरे स्थान पर मोहम्मद कैफ हैं जिन्होंने 2002 में नाबाद 87 रनों की पारी खेली थी। रोहित ने इंग्लैंड में आठवां शतक लगाया और वह किसी एक विदेशी देश में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित से ज्यादा इंग्लैंड में वनडे शतक जो रूट ने लगाए हैं। रूट इंग्लैंड में 10 वनडे शतक लगा चुके हैं। सचिन तेंदुलकर ने यूएई में सात वनडे शतक लगाए हैं। रोहित लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने के वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। रोहित ने 39 साल और 80 दिन की उम्र में ऐसा किया है। इतना ही नहीं रोहित सभी प्रारूप मिलाकर भारत के लिए शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज हैं। रोहित और गिल ने इस मैच में शतकीय साझेदारी की। ये भारत के लिए लॉर्ड्स में वनडे में की गई दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। भारत के लिए इस मैदान पर वनडे में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। रैना और धोनी ने 2014 में इस मैदान पर पांचवें विकेट के लिए 169 रनों की साझेदारी की थी। रोहित और विराट कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी हुई।

2019 के बाद भारत से इंग्लैंड ने जीती वनडे सीरीज

लंदन। इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में भारत को 27 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड ने इस तरह तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने इससे पहले पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी भारत को 4-0 से हराया था और अब वनडे में भी अपना दबदबा दिखाया। इंग्लैंड ने 2019 के बाद पहली बार भारत के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम की है। रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने 50 ओवर में तीन विकेट पर 387 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में सात विकेट पर 360 रन ही बना सकी। भारत के लिए रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि शुभमन गिल और विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। लेकिन(कोहली टिके थे तो भारत की उम्मीदें बंधी हुई थी। लेकिन कोहली के आउट होते ही भारत के हाथ से मैच निकल गया क्योंकि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, के एल राहुल और अक्षर पटेल सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए।

परिसीमन के मुद्दे को और स्पष्ट करे केंद्र: शिवा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। एमके स्टालिन की अगुवाई वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने केंद्र सरकार से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के अपने रोडमैप को स्पष्ट करने की मांग की। पार्टी का कहना है कि यह कोटा भविष्य में होने वाले परिसीमन से जोड़ने के बजाय निचले सदन की मौजूदा सदस्य संख्या पर आधारित होना चाहिए। यह मांग डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान उठाई।

संसद का यह सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीएमके लोकसभा में मौजूदा संख्या-बल के आधार पर महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है, लेकिन हम परिसीमन के मुद्दे पर और स्पष्टता चाहते हैं। शिवा ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया का दक्षिणी राज्यों पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए और उन्होंने सरकार से इस बारे में और स्पष्टता की मांग की। शिवा ने कहा कि अगर इससे दक्षिणी राज्यों पर असर पड़ता है, तो इसे 25 साल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। इससे पहले, डीएमके ने तय किया था कि पार्टी मौजूदा रूप में परिसीमन बिल का विरोध जारी रखेगी—जो आबादी पर आधारित है और महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा है। पार्टी नए बिल का इंतज़ार करेगी और उसमें दी गई सिफारिशों के आधार पर आगे का फ़ैसला लेगी। कांग्रेस ने भी परिसीमन बिल का विरोध करने का ऐलान किया है और कहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष की एकता बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस, सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को एक साथ करने से जुड़े प्रस्तावित बिल का भी विरोध करेगी।

» डीएमके ने लोस और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण पर भाजपा से किया सवाल

एनसीपीआई एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, मान्यता मिले : सुदीप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद, बागी तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि उनके गुट ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (इंडिया) के लिए औपचारिक मान्यता की मांग की है। उनका दावा है कि यह नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।

बंद्योपाध्याय ने कहा कि मान्यता दिलाने के लिए लोकसभा स्पीकर को एक पत्र सौंपा जाएगा। बंद्योपाध्याय ने कहा कि यह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टियों से बड़ी है। हमने मांग की है कि चुनाव आयोग एनसीपीआई को मान्यता दे। वह पत्र स्पीकर के सामने पेश किया जाना है और वह कागज़ यहां है। काकोली इसे सौंपने जा रही हैं।

जनहित के मुद्दों पर मोहन सरकार को घेरेंगे : उमंग सिंघार

» विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। रविवार को भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल पूरी तैयारी और एकजुटता के साथ विधानसभा में पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक आरोप नहीं लगाएगा, बल्कि हर मुद्दे पर तथ्य और प्रमाण रखकर सरकार से जवाब मांगेगा।

उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, किसानों की परेशानियां, महिलाओं की सुरक्षा, भर्ती में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और आदिवासी-दलितों के अधिकार जैसे मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को सदन में इन सभी सवालों का जवाब देना ही होगा। बैठक में तय किया गया कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, भ्रष्टाचार और कथित जमीन घोटाले समेत जनहित के सभी बड़े मुद्दों पर लगातार घेरा जाएगा। कांग्रेस ने दावा किया कि विपक्ष इस बार केवल आरोप नहीं लगाएगा, बल्कि तथ्यों और दस्तावेजों के साथ सरकार से जवाब मांगेगा।

भगवा को लेकर सियासत हुई 'लाल'

» बिहार में भाजपा व जदयू में अनबन की आहट!

» स्कूलों पर भगवा रंग जदयू ने जताई आपत्ति

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार में 551 मॉडल स्कूलों का नाम बदलकर सरस्वती विद्या निकेतन रखने और उन्हें केसरिया रंग में रंगने के फैसले ने राज्य की सियासत लाल हो गई है। जहाँ भाजपा इसे बुनियादी ढांचा सुधार बता रही है, वहीं सहयोगी जदयू ने शिक्षा का कोई रंग नहीं होता कहकर आपत्ति जताई है, जो एनडीए के भीतर मतभेदों की ओर संकेत करता है।

यह घटनाक्रम बिहार शिक्षा विवाद और शिक्षा के विपक्ष और सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल सहयोगी दल, दोनों ने ही इसकी आलोचना की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम का बचाव करते हुए इसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी पहल का हिस्सा बताया है।

बेगूसराय में मुख्यमंत्री ने किया स्कूल का उद्घाटन

बेगूसराय में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए नए नाम वाले स्कूलों का औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद एक्स पर एक पोस्ट में चौधरी ने लिखा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पवित्र भूमि बेगूसराय से मैंने 551 सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूलों) का उद्घाटन किया, जिससे बिहार में शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत हुई है। बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब बिहार पढ़ेगा के संकल्प के साथ, ऐप, बिहार स्कूल लाइव क्लासेस और स्मार्ट क्लासेस जैसी आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने दिया निर्देश

बिहार शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सरस्वती विद्या निकेतन से नाम बदलकर रखे गए सभी स्कूल एक जैसी बनावट और रंग-रूप (आर्किटेक्चरल और कलर स्कीम) का पालन करें। एक मॉडल स्कूल के हेडमास्टर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि स्कूल अधिकारियों को जल्द से जल्द इमारतों को दोबारा रंगने का निर्देश दिया गया था। पहले स्कूलों के लिए रंग को लेकर कोई तय नियम नहीं थे, और इमारतों को पीले, गुलाबी और आसमानी नीले जैसे रंगों में रंगा जाता था। नए निर्देश के तहत, सभी स्कूलों की बाहरी दीवारों पर केसरिया रंग, क्लासरूम के अंदर सफेद रंग और मुख्य गेट पर सुनहरा रंग किया जाना है। हेडमास्टर ने कहा कि पहले रंग चुनने का फैसला काफी हद तक स्कूल के प्रमुखों पर छोड़ा जाता था, लेकिन नए आदेश का मकसद सभी मॉडल स्कूलों में एक जैसा रंग-रूप लाना है।

शिक्षा को रंगों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए : संजय झा

बिहार में सरकारी मॉडल स्कूलों को केसरिया रंग में रंगे जाने की खबरों के बीच, सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि शिक्षा को रंगों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने नीट परीक्षा के मुद्दे को संभालने के केंद्र के तरीके का समर्थन किया। झा ने कहा कि शिक्षा का कोई रंग नहीं होता। नीतीश कुमार ने ऐसे मॉडल स्कूल शुरू किए थे। शिक्षा सभी के लिए है। मुझे नहीं लगता कि इसे कोई रंग दिया जाना चाहिए।

स्कूल की इमारतों के रंग पर ध्यान देने के बजाय अच्छी शिक्षा देने की होनी चाहिए : नीरज कुमार

जदयू नेता नीरज कुमार ने ज़ोर देकर कहा कि प्राथमिकता स्कूल की इमारतों के रंग पर ध्यान देने के बजाय अच्छी शिक्षा देने की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है, जो सभी धर्मों और समुदायों को शिक्षा पाने की गारंटी देता है। कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत, जो संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है, यह है कि सभी धर्मों और समुदायों के लोगों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। सिर्फ रंग-रूप बदलने से उस अधिकार की गारंटी नहीं मिलती। असल बात यह पक्का करना है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।

धर्मेंद्र के इस्तीफे को लेकर सोनम वांगचुक नरम पड़े

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र के इस्तीफे की प्राथमिक मांग से सोनम वांगचुक पीछे हट गए हैं। उन्होंने आज सुबह अपना अनशन खत्म करने और संसद तक

प्रस्तावित मार्च से पहले तीन शर्तें जारी की हैं, उनमें यह शर्त कहीं नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। इसी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी भी अब सिर्फ उनकी जवाबदेही तय करने की बात कहकर स्टैंड को सॉफ्ट कर लिया है।

20 जुलाई, 26 (सोमवार) तड़के ढाई बजे सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर से एक बयान जारी किया। इसमें लिखा गया है-सरकार से कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों में बदलाव नहीं हुआ है। आत्महत्या के द्वारा 20 से ज्यादा स्टूडेंट की मौत को लेकर हम धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही चाहते हैं और उनके परिवारों में से प्रत्येक के लिए 1 करोड़ रुपये की सहायता चाहते हैं। हमारा आंदोलन तबतक नहीं रुकेगा, जबतक हमें न्याय नहीं मिल जाता। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ही एक महीने पहले यह आंदोलन शुरू किया था।

तमिलनाडु में सियासी भूचाल

» मुख्यमंत्री विजय पर टिप्पणी मामले में डीएमके विधायक मार्कंडेयन गिरफ्तार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में सोमवार को उस समय भारी गरमाहट आ गई, जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के विधायक मार्कंडेयन को पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई राज्य के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में की गई है।

इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद थूथुकुडी जिले के विलाथिकुलम इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विलाथिकुलम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक मार्कंडेयन पूर्व मुख्यमंत्री और ह्रस्व के दिवंगत दिग्गज नेता एम. करुणानिधि की जयंती के अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विजय को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक बयानबाजी की।

मुख्यमंत्री की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम (टीवीके) के कार्यकर्ताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विधायक को हिरासत में ले लिया। कार्यक्रम के दौरान, मार्कंडेयन ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री विजय का जिक्र करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद TVK सदस्यों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि मामले की आगे की जांच जारी है।

राज्य बहाल करने की मांग को लेकर नेकां का प्रदर्शन कर अगुवाई करेंगे फारूक अब्दुल्ला

» सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी में अचानक आई बाढ़ की वजह से सीएम लौटे जम्मू-कश्मीर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला सोमवार को नई दिल्ली में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली का अपना दौरा छोटा कर दिया है। सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी में अचानक आई भीषण बाढ़ में 12 लोगों की मौत के बाद वे जम्मू लौट रहे हैं।

उमर ने पर पोस्ट किया कि मौसम विभाग की चेतावनी और जम्मू डिवीज़न के कुछ हिस्सों में बन रहे गंभीर हालात को देखते हुए, मैं आज दोपहर दिल्ली से जम्मू के लिए उड़ान भरूंगा ताकि हालात का खुद जायज़ा ले सकूं। राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विरोध प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में योजना के मुताबिक ही होगा। उमर के इस ऐलान के बाद कि फारूक अब्दुल्ला राज्य का दर्जा बहाल करने के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे।

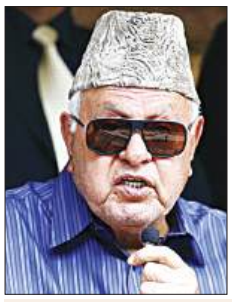

विपक्षी पार्टियों ने नेकां पर साधा निशाना

विपक्षी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सज्जाद लोन ने एक तंज भरे पोस्ट में कहा, पापा दिल्ली में विरोध करेंगे और बाबा जम्मू में अच्छे बच्चे की तरह पेश आएंगे। सादिक ने कहा कि अगर आप अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही और अपनों को खोने के गम से जूझ रहे लोगों के साथ खड़े होने के मुख्यमंत्री के फैसले को राजनीति का मुद्दा बनाते हैं, तो आप बुनियादी इंसानियत को भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और सीएम ने इस लड़ाई का नेतृत्व किया है। लेकिन सरकार के मुखिया के तौर पर, मुश्किल घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ खड़े होना भी उनकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। मृतकों पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर स्टेटहुड की मांग पर कांग्रेस का हल्लाबोल

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महाराजा हरि सिंह पार्क में धरना दिया और बाद में लोक भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस का यह मार्च राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए निकाला जा रहा था, जिसमें जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने ज्वेल चौक पर बैरिकेड लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ देर के लिए हल्की धक्का-मुक्की हुई। पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव जीए मीर, कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला समेत कई पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को हिरासत में लिया।

बेबुनियाद और फर्जी खबरें चला रही मीडिया : जयराम

» परिसीमन बील के समर्थन में खबरों पर बिफरे कांग्रेस नेता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने सांकेतिक वॉकआउट किया, जिसका मुख्य कारण नेशनल सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया की भागीदारी थी। जयराम रमेश ने एनसीपीआई को 20 बागी तृणमूल कांग्रेस सांसदों के लिए एक पार्किंग प्लेस बताया, जिनकी सदस्यता पर लोकसभा स्पीकर का फैसला लंबित है।

इस घटना ने बैठक के माहौल में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया, हालांकि विपक्षी दल बाद में चर्चा में शामिल हो गए। उन्होंने इन खबरों को बेबुनियाद और फर्जी बताया। पर एक पोस्ट में, रमेश ने आरोप लगाया कि कुछ टीवी चैनल ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जो साफ तौर पर प्लांटेड हैं और जिनमें कहा गया है कि बैठक के दौरान परिसीमन विधेयक का समर्थन किया गया। रमेश ने अपने पोस्ट में कहा कि कुछ टीवी चैनल साफ तौर पर प्लांटेड खबरें दिखा रहे हैं कि चल रही सर्वदलीय बैठक में परिसीमन विधेयक का समर्थन किया गया है। यह पूरी तरह से बेबुनियाद और फर्जी खबर है। केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक का मकसद दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए राजनीतिक दलों का सहयोग मांगना और सरकार के विधायी एजेंडे पर चर्चा करना था।

केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से विपक्षी दलों ने सांकेतिक वॉकआउट किया। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा नेशनल सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया (एनसीआई को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाए जाने का विरोध किया। कुछ मिनट बाद वे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए वापस आ गए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से सभी विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। उन्होंने केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध किया जिसके तहत नेशनल सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया को बैठक में बुलाया गया था।

महाराष्ट्र में भीषण हादसा, ट्रक और कार की टक्कर से लगी आग, छह की मौत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। महाराष्ट्र में वर्धा समृद्धि हाइवे पर एक भीषण हादसा हुआ है। वर्धा के पास हाईवे पर एक कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर के बाद 6 लोगों की जलकर मौत हो गई। कार और ट्रक में टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और कार धू-धू कर जलने लगी। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई, जिससे दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार चार लोगों की गाड़ी जलते हुए ट्रक के नीचे फंसने से दर्दनाक मौत हो गई।

इस घटना से हर तरफ शोक और सदमे का माहौल है। आग लगने से ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि कार जलते हुए ट्रक के नीचे फंस गई, जिससे उसमें सवार चारों लोगों की मौत हो गई, इस घटना में कुल छह लोगों की मौत हुई है। हादसा वर्धा जिले की सीमा में समृद्धि महामार्ग पर हुई, इथेनॉल से भरा एक ट्रक पहले ही दुर्घटनाग्रस्त होकर हाईवे पर खड़ा था, जिसके कारण अधिकारियों ने ट्रैफिक का रास्ता बदल दिया था। इसी बीच, पुणे से वर्धा की तरफ जा रही एक कार जोरदार रफ्तार से ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां तुरंत आग की लपटों में घिर गईं।

महाराष्ट्र कार्यालय:- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। विधि सलाहकार: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा